

प्रेषक,

अमित सिन्हा
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 19 जून, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-2012 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अंतर्गत जनपद देहरादून में थाना कालसी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:डीजी-दो-130-2007, दिनांक 29 फरवरी, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अंतर्गत जनपद देहरादून में थाना कालसी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था 'उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग' सहिया द्वारा उपलब्ध कराये गये रुपये 4.05 लाख के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रुपये 3.36 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में रुपये 3.36 लाख (रुपये तीन लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो. नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7- वित्त विभाग की वेबसाईट पर आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी गयी है। आवंटन शीट संलग्न है।

8- उक्त व्यय वर्ष 2012-13 के आय-व्यय में अनुदान सं०-10 लेखाशीर्षक 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102 -13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पुलिस थाना/चौकी निर्माण, 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:- 22/N.P/xxvii(5)/12, दिनांक 06 मई, 2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय
(अमित सिन्हा)
अपर सचिव

संख्या:- 605(1)/XX-2012-4(5)2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सहिया, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक:यथोक्त।

आज्ञा से,
(जे० पी० जोशी)
संयुक्त सचिव